



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262294
CG-DL-E-04042025-262294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/चैत्र 14, 1947

No. 1593]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/CHAITRA 14, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

का.आ. 1612(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिंगोलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के आसपास एक पारिस्थितिक संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है; और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1942(अ), तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. मानीटरी समिति. – (1) केंद्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| (i) | कलेक्टर, राजकोट जिला | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (iii) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य, पदेन; |
| (iv) | प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर गुजरात सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि। | सदस्य; |
| (v) | प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर गुजरात सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या पक्षीविज्ञान या वन्य जीवन में एक विशेषज्ञ। | सदस्य; |
| (vi) | क्षेत्र का वरिष्ठ नगर नियोजक | सदस्य, पदेन; |
| (vii) | सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड | सदस्य, पदेन; |
| (viii) | उप वन संरक्षक, जामनगर एवं देवभूमि द्वारका | सदस्य सचिव, पदेन। |

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

- (3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।”

[फा. सं. 25/94/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 20 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1942(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2025

S.O. 1612(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Hingolghadh Wildlife Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017, namely:-

In the said notification, For paragraph 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

“5. Monitoring Committee. – (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

- | | |
|--|-------------------------------|
| (i) Collector, Rajkot District | Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (ii) Representative of the Department of Forests and Environment,
Government of Gujarat | Member, <i>ex officio</i> ; |

(iii)	Regional officer, State Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
(iv)	One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years	Member;
(v)	One expert in ecology or ornithology or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years	Member;
(vi)	Senior Town Planner of area	Member, <i>ex-officio</i> ;
(vii)	Member, State Biodiversity Board	Member, <i>ex-officio</i> ;
(viii)	Deputy Conservator of Forests, Jamnagar and Devbhumi Dwarka	Member Secretary, <i>ex-officio</i> .

6. Functions of Monitoring Committee.— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department concerned, representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-IV.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/94/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1942(E), dated the 20th June, 2017.